Ministry of Environment & Forests have notified the draft Bio-Medical Wastes (Management and Handling) Rules, 1995

Eradication of Malaria

52. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of cases of malaria has been increasing in every State and Union Territory;

(b) if so, the main reasons for the increasing incidents of malaria;

(c) the steps taken by Government to stop the spread of malaria; and

(d) the afforts made for providing proper treatment to the malaria patients and to eradicate malaria?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) There have been reports of sporadic outbreaks of malaria in some parts of the country; however, incidence of malaria has been contained around 2 million cases annually since 1984.

(c) and (d) Steps taken by Government to stop spread of the disease and for providing proper treatment for malaria patients, inter-alia, include, (1) early detection and prompt treatment, (2) vector control by use of proper insecticides, (3) intensification of health education activities, and (4) provision of 100% assistance to seven north-eastern States etc.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के संबंध में लम्बित पड़े प्रस्ताव

53. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सरकारी और निजी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास इस समय लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी राज्य में सीधे कोई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित नहीं करता। अल्कोहलयुक्त पेयों के किण्वन तथा आसवन, चीनी तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंस मुक्त हैं तथा उद्यमियों को केवल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करना होता है। फिर भी, जिन उद्योगों के मामले में औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता होती है या 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए या विदेशी सहयोग आदि के लिए अनुमोदन दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में उदारीकरण से लेकर मार्च, 96 तक दाखिल किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा दिए गए अनुमोदनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या	अनुमोदनों की संख्या
उ०प्र०	673	62
पंजाब	287	18
हरियाणा	386	73
हिमाचल प्रदेश	39	19
राजस्थान	322	43

प्राप्त किए गए 37 अन्य प्रस्तावों के संबंध में भी कार्रवाई शुरू की गई है।

Resurgence of Eradicated Diseases

54. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Indian Express (New Delhi) dated the 23.6.96 under the caption 'Eradicated infectious diseases making a comeback' stating that viral resistance to conventional drugs makes treatment difficult; and

(b) if so, the steps Government propose to take to check such diseases?